प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

27.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

''आज के मुख्य समाचार''

- प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अधिक बिल आने पर पुराने बिलों का आकलन कर कमियों को दूर करेगी राज्य सरकार।
- हिमकेयर योजना में घोटाले संबंधी आरोपों को लेकर विधानसभा में हंगामा–विपक्ष ने जांच की मांग की।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान–प्रदेश में विभिन्न तरह के माफिया में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई।
- राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने रोजगारोन्मुखी व सतत् विकास को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली पर दिया बल।
- केन्द्र सरकार ने पैट्रोल व डीजल पर एक्साईज डयूटी घटाई–अधिसूचना जारी।

अब समाचार विस्तार से.....

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अगर किसी का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है तो उसके पिछले एक साल के बिजली के बिल के साथ आकंलन कर कमियों को दूर किया जाएगा। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक राम कुमार के अनुपूरक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने पहले ही स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर मानक तय किए है। उन्होंने कहा कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगाते है तो केंद्र सरकार पैसे में कटौती करेगी। विधायक राम कुमार के एक अन्य सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार नियमों में संशोधन करेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडू, कर्नाटक और हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में इस तरह के संशोधन किए जा चुके हैं। विधायक कुलदीप सिंह राठौर के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सत्यानंद स्टोक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिलारू में युक्तिकरण करके स्टाफ को रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र का भवन बनकर तैयार हो चुका है।

हंगामा

इससे पूर्व प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण के दौरान हिमकेयर योजना में 11 सौ करोड़ के घोटाले संबंधी आरोपों को बेबुनियाद व तथ्यों से विपरीत बताया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 11 सौ करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों पर सरकार से जवाब देने को कहा है।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 सौ करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वास्तविक अनियमितता करीब एक सौ 20 करोड़ रुपये की है।

मुख्यमंत्री–जवाब

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एलान किया कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वे आज विधानसभा में भाजपा द्वारा पुलिस व सम्बद्ध संगठनों पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी प्रदेश की संपदा को लूटेगा तो सरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्तव्यनिष्ठा व सत्यनिष्ठा की शपथ ली है और कई बडे खुलासे आने वाले समय में होंगे। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर विभिन्न तरह के माफिया में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तभी प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरूस्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण है और 2023 से 25 तक पूर्व सरकार से कहीं कम मामले दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधों में तुलानत्मक 6 फीसदी की कमी आई है। कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक बताते हुए उन्होंने कटौती प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह किया लेकिन इस पर भाजपा ने अपना विरोध दर्ज किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वोट करवाया और सत्तापक्ष के समर्थन से कटौती प्रस्ताव गिर गया।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा है कि रोजगारोन्मुखी व संवेदनशील और सतत् विकास का बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज लोक भवन शिमला में विद्या भारती प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान के समग्र शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित शिक्षा महाकुंभ 2026 के ब्रोशर के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा को नई दिशा देने में शिक्षा महाकुंभ जैसे आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बीच राज्यपाल ने आज शिमला के गेयटी थियेटर में सुनील उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी व युवा सम्मान समारोह को सम्बोधित किया। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए उन्हें संस्कारों व संयुक्त परिवारों से जोड़ने की जरूरत बताई।

इस दौरान उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई युवा प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया।

एक्साइज डयूटी

केंद्र सरकार ने पैट्रोल व डीजल पर एक्साइज डयूटी कम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार अब पैट्रोल पर एक्साइज डयूटी 13 रूपए से घटाकर शून्य कर दी गई है जबकि डीजल पर 10 से घटाकर 3 रूपए प्रति लीटर की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

भाजपा

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पश्चिम एशिया में चल रही अस्थिर परिस्थितियों के बीच केन्द्र द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने के निर्णय को सराहनीय व दूरदर्शी बताया है। उन्होंने कहा कि डीजल व पैट्रोल की कीमतों में कमी से जनता को महंगाई से राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था स्थिर होगी। जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार द्वारा डीजल पर सैस लगाकर कीमतें बढ़ाने के प्रयास को दुर्भाग्यपूर्ण और जनविरोधी बताया है। इस बीच पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने केन्द्र द्वारा पैट्रोल व डीजल पर एक्साइज डयूटी में की गई कटौती का स्वागत करते हुए इसे जनहित में लिया गया सराहनीय निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जहां जनता को राहत देने का काम कर रही है वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है।

इंदुबाला

केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत हिमाचल प्रदेश में एक हजार 5 सौ 38 किलोमीटर लम्बी दो सौ 94 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सांसद इंदुबाला गोस्वामी द्वारा संसद में पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण के लिए करीब 2 हजार 2 सौ 47 करोड़ 24 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बाजार, स्वास्थ्य केन्द्रों, शिक्षा संस्थानों और विकास केन्द्रों में आवाजाही सुगम बनाना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सड़कों के अपग्रेडेशन का प्रावधान नहीं किया गया है।

सरकार एलपीजी आबंटन

केन्द्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20 प्रतिशत आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुगम बनाना है। उन्होंने कहा कि उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पाइपलाइन गैस विकल्प नहीं है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि जहां दुनिया के अन्य देश चार दिन के कार्य सप्ताह, स्कूल और कार्यालय बंद करने

और ईंधन की कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि जैसे कड़े ईंधन संरक्षण उपाय कर रहे हैं, वहीं भारत ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता और सामर्थ्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है।

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अधिक बिल आने पर पुराने बिलों का आकलन कर कमियों को दूर करेगी राज्य सरकार।
- हिमकेयर योजना में घोटाले संबंधी आरोपों को लेकर विधानसभा में हंगामा–विपक्ष ने जांच की मांग की।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान–प्रदेश में विभिन्न तरह के माफिया में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई।
- राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने रोजगारोन्मुखी व सतत् विकास को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली पर दिया बल।
- केन्द्र सरकार ने पैट्रोल व डीजल पर एक्साईज डयूटी घटाई–अधिसूचना जारी।